**पूर्ण बेंच**

**समक्ष *एस. एस. संधावालिया, सी.जे., पी.सी. जैन, एस.सी.***

**गुरचरण सिंह —*प्रार्थी।***

***बनाम***

**हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तरदाता-***

***सिविल रिट सं.* 1977 *का* 2207**

**17 जुलाई, 1978**

*पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (1961* का XXV) - *धारा 27 (1)* और *(1 ए)* - किसी सदस्य या समिति को निलंबन के लिए कार्यवाही के दौरान निलंबित करना - निलंबन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस - क्या अनिवार्य है।

निर्धारित पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1961 (हरियाणा में लागू) की धारा 27 (1) और (1 ए) की सरल भाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि विधायिका ने अपने विवेक से अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के तहत प्रबंध समिति की अनदेखी या उसके सदस्य को हटाने के संबंध में कारण बताने का अवसर देने का प्रावधान किया है। तथापि, जब संशोधन के माध्यम से धारा में उप-धारा (1क) जोड़ी गई थी, तो संविधि निर्माताओं ने प्रबंध समिति या उसके किसी सदस्य के निलंबन के संदर्भ में दिए जा रहे कारण बताओ कारणों को दर्शाने के लिए उचित अवसर के पूर्व के सिद्धांत का उपयोग नहीं किया था। जहां तक निलंबन का संबंध है, कारण बताओ नोटिस का प्रावधान इसलिए इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है, यह निर्माण की एक स्थापित तोप है कि जब विधायिका अलग-अलग भाषा का उपयोग करती है और विशेष रूप से सन्निहित प्रावधानों में यदि यह माना जाता है कि उसने ऐसा डिजाइन किया है। जबकि धारा 27 (1) में कारण दिखाने का अवसर स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, फिर भी उपधारा (1 ए) में इसे डिजाइन रूप से बाहर रखा गया है और इसलिए, अंतिम परिणाम समान नहीं हो सकता है। शब्दावली में इस अंतर से एकमात्र निष्कर्ष स्पष्ट है, अर्थात्, उप-धारा (1 ए) के तहत निलंबन के संदर्भ में, विधायिका ने आवश्यक निहितार्थ द्वारा दिखाने, कारण दिखाने के किसी भी अवसर को बाहर रखा है। दूसरे शब्दों में, जबकि प्रबंध समिति या उसके सदस्यों के अधिक्रमण और निष्कासन के अधिक भौतिक मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सहारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाता है, इसे प्रबंध समिति या उसके किसी भी सदस्य के निलंबन के अपेक्षाकृत मामूली और मध्यस्थ चरण में बाहर रखा जाता है।

(पैरा 5)

*शादीपुर सहकारी समिति। क्रेडिट सोसाइटी* v. *1976 के हरियाणा राज्य और अन्य* सीडब्ल्यू

8358 ने 29 जनवरी, 1977 को निर्णय लिया।

*अंगरेज सिंह और अन्य हरियाणा राज्य और अन्य* 1978 पी.एल.जे. दो दोनों ने खारिज कर दिया।

*तेवतिया और माननीय न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों द्वारा* 13 सितंबर, 1977 *को मामले में ईडी से जुड़े कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला सौंपा गया था। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया, माननीय न्यायमूर्ति पीसी जैन और माननीय न्यायमूर्ति एससी मिताई की वृहद पीठ ने अंततः 1 जुलाई,* 1978 को मामले का फैसला किया। *

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय कृपया आक्षेपित आदेश अनुलग्नक "पी-एल" को रद्द करने की कृपा करे, जिसके आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता की प्रबंध समिति को प्रतिवादियों द्वारा निलंबित कर दिया गया है।*

*इसके अलावा, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक आक्षेपित आदेश अनुबंध* "पी-एल" *के संचालन पर रोक लगाई जाए। रिट याचिका की लागत को याचिकाकर्ता को अनुमति दी जा सकती है।*

*आगे यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता अनुबंध "पी-1"* की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त नहीं कर सका *और याचिका के साथ संलग्न प्रति मूल की एक सच्ची और सही प्रति है।*

*यह भी प्रार्थना की जाती है कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए रिट क्षेत्राधिकार नियमों को हटा दिया जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर *से जीएस संधू, वकील.*

उत्तरदाताओं के लिए *ए.एस. नेहरा, अतिरिक्त ए.जी., हरियाणा।*

**निर्णय**

*एस.एस. संधावालिया, सी.जे.*

1. पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (हरियाणा में लागू) की धारा 27 (हरियाणा में लागू) के तहत अधिक्रमण की कार्यवाही के दौरान किसी सहकारी समिति के सदस्य या समिति को निलंबित करने से पहले क्या कारण बताओ नोटिस जारी करने का अवसर अनिवार्य है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । पूर्ण पीठ के इस संदर्भ में निर्धारण।

2. तथ्य गंभीर विवाद में नहीं हैं और उनका एक पारित संदर्भ पर्याप्त है। याचिकाकर्ता गुरचरण सिंह हंसला सहकारी कृषि सेवा समिति लिमिटेड, हंसला की प्रबंध समिति के पांच सदस्यों में से एक हैं। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कुरुक्षेत्र ने रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त समिति के अधिक्रमण के लिए कार्यवाही शुरू की। उक्त समिति को दिनांक 19 जुलाई, 1977 के अनुलग्नक पी-1 में यह बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि क्यों न इसे हटा दिया जाए और इसमें मोनिंग समिति द्वारा की गई कई अनियमितताओं और अवैधताओं को सूचीबद्ध किया गया था। समिति के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए आमंत्रित किया गया था और अधिनियम की धारा 27 के तहत अपेक्षित सूचना अनुलग्नक पी 1 में विनिदष्ट आरोपों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। तथापि, प्राधिकरण ने आगे यह विचार व्यक्त किया कि प्रबंध समिति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक्रमण और हटाने के लिए कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अधिनियम की धारा 27(1ए) के तहत कार्य करते हुए प्राधिकरण ने प्रबंध समिति को निलंबित कर दिया और श्री कुलदीप राय वैद को नियुक्त किया। कुरुक्षेत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के विकास अधिकारी को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया है। केवल उपरोक्त निलंबन ही इस रिट याचिका में चुनौती का विषय है।

3. जब यह मामला पहली बार एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया प्राथमिक और वास्तव में एकमात्र आधार यह था कि उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई बिना किसी नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई थी। इस तर्क के लिए निर्भरता पूरी तरह से दो डिवीजन बेंच के फैसलों पर आधारित थी। *शादीपुर सहकारी ऋण समिति* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य*[1] की खंडपीठ ने प्रस्ताव की सुनवाई के चरण में एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि सोसायटी के मामलों की देखभाल करने के लिए प्रबंध समिति के निहित अधिकारों को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच नहीं की गई हो। नतीजतन, बेंच ने निलंबन के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए आगे बढ़े, जिससे संबंधित अधिकारियों को कानून के अनुसार एक नया आदेश पारित करने का विकल्प खुला छोड़ दिया गया। उसी खंडपीठ ने अपने पहले के दृष्टिकोण को दोहराया, भले ही इसकी यथार्थता को उनके समक्ष प्रस्ताव स्तर पर फिर से चुनौती दी गई थी, केवल निर्णय रिपोर्ट में अंगरेज *सिंह और अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य के रूप में*[2]

[1] सीडब्ल्यू 8358 1976 29 जनवरी, 1977 को तय किया गया था।
[2] 1978 पी.एल.जे.

4. संदर्भ यी आदेश द्वारा खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने दो निर्णयों में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर गंभीरता से संदेह किया और इसलिए मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेज दिया। इस प्रकार मामला हमारे समक्ष है।

*5.* यह स्पष्ट है कि यहां वास्तविक और वास्तव में एकमात्र सवाल *शादीपुर को-ऑपरेटिवटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटी और अंगरेज सिंह की सहजता* (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों की शुद्धता है। हालांकि, उपरोक्त निर्णयों के आलोचनात्मक विश्लेषण का सहारा लेने से पहले, किसी को अनिवार्य रूप से क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर बारीकी से नज़र डालनी चाहिए, जिसके चारों ओर विवाद आवश्यक रूप से घूमना चाहिए। हरियाणा में लागू पंजाब सहकारी समिति अधिनियम की धारा 27 (1) और (1 ए) निम्नानुसार है: –

"27. *समिति का अधिक्रमण।* (1) यदि रजिस्ट्रार की राय में कोई समिति या उसका कोई सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों के पालन में लगातार चूक करता है या लापरवाही बरतता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो समाज या उसके सदस्यों के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है, रजिस्ट्रार समिति या सदस्य को जैसा भी मामला हो, देने के बाद, लिखित में आदेश द्वारा अपनी आपत्तियां, यदि कोई हो, बताने का अवसर दे सकता है-

i. समिति को हटा दें, और -

ii. समिति के लिए नए सिरे से चुनाव का आदेश दें; नहीं तो

iii. एक या एक से अधिक प्रशासकनियुक्त करें, जिन्हें सोसाइटी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, जो आदेश में निर्दिष्ट एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सोसाइटी के मामलों का प्रबंधन करें- जो अवधि रजिस्ट्रार के विवेकपर समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है, ताकि, हालांकि, कुल अवधि पांच साल से अधिक न हो;

iv. सदस्य को हटादें और इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उपनियमों के अनुसार निवर्तमान सदस्य की शेष अवधि प्राप्त करें।

(IA) जहां रजिस्ट्रार उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने के लिए कार्यवाही करते समय यह राय रखता है कि कार्यवाहियों की अवधि के दौरान समिति के सदस्य या सदस्य का निलंबन सहकारी समिति के हित में आवश्यक है, वह समिति या सदस्य को, जैसा भी मामला हो और जहां समिति निलंबित है, ऐसी व्यवस्था करे जो वह कार्यवाही होने तक सोसायटी के कार्यों के प्रबंधन के लिए उचित समझे। पूरा किया:

बशर्ते कि यदि इस तरह से निलंबित समिति या सदस्य को नहीं हटाया जाता है, तो उसे बहाल कर दिया जाएगा और निलंबन की अवधि उसके कार्यकाल में गिनी जाएगी।

उपरोक्त उपबंधों की सीधी भाषा पर एक बार में एक नज़र डालने से भी यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में आती है! तथ्य यह है कि विधायिका ने अपने विवेक से अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन प्रबंध समिति के अधिक्रमण या उसके सदस्य को हटाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है। तथापि, जब 1972 के हरियाणा अधिनियम 22 के तहत संशोधन के खंड में उपधारा (1क) को सम्मिलित किया गया था, तो संविधि निर्माताओं ने प्रबंध समिति या किसी सदस्य के निलंबन के संदर्भ में कारण बताने के लिए उचित अवसर के पूर्व वाक्यांश का उपयोग नहीं किया था। इसलिए, जहां तक निलंबन का संबंध है, कारण बताओ नोटिस का प्रावधान इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। मुझे यह निर्माण के एक स्थापित सिद्धांत के रूप में प्रतीत होता है कि जब विधायिका अलग-अलग भाषा का उपयोग करती है और विशेष रूप से सन्निहित प्रावधानों में इसे डिजाइन करके किया जाना चाहिए। यह कहना शायद ही संभव लगता है कि धारा 27 (1) में कारण दिखाने का अवसर स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, फिर भी उप-धारा (1 ए) में जहां इसे डिजाइन रूप से बाहर रखा गया है, अंतिम परिणाम अभी भी वही होना चाहिए। वास्तव में शब्दावली में इस अंतर से एकमात्र निष्कर्ष स्पष्ट प्रतीत होता है, अर्थात्, उप-धारा (1 ए) के तहत निलंबन के संदर्भ में, विधायिका ने आवश्यक निहितार्थ द्वारा कारण दिखाने के किसी भी अवसर को बाहर रखा है। इसलिए, मेरा विचार है कि उप-धारा (1ए) के प्रावधानों को जब विशेष रूप से उप-धारा (1) के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सहारा लेते हुए प्रबंध समिति या उसके सदस्यों के अधिक्रमण और निष्कासन के अधिक भौतिक मामले में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, लेकिन इसे प्रबंध समिति या इनमें से किसी एक के निलंबन के अपेक्षाकृत मामूली और मध्यस्थ चरण में बाहर रखा गया है। इसके सदस्य। यह ध्यान देने योग्य है कि निलंबन प्रबंध समिति या उसके किसी भी सदस्य की अनदेखी या हटाने के लिए धारा 27 (1) के तहत की गई कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ कदमों में से एक है।

(6) व्यापक परिपेरक्ष्य में भी यह स्पष्ट है कि निलंबन की कार्यवाही के दौरान प्रबंध समिति का निलंबन एक आकस्मिक या अत्यावश्यक मामला प्रतीत होता है जो प्राधिकारी के इस बात से संतुष्ट होने पर आवश्यक हो सकता है कि सहकारी समिति के हित में यह आवश्यक है। यह वास्तव में अधिनियम की उप-धारा (1ए) में कानून द्वारा ही प्रदान किया गया है। स्पष्ट रूप से सोसाइटी के धन के किसी भी दुरुपयोग या इसकी संपत्ति और इसके कामकाज को अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए, रजिस्ट्रार को प्रबंध समिति को निलंबित करने और इसके मामलों के

प्रबंधन के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान की जाती है। यदि आवश्यक हो। यदि इस तरह की तत्काल या आकस्मिक कार्रवाई के संदर्भ में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अपेक्षाकृत धीमी आवश्यकताओं के लिए कारण बताओ, नोटिस जारी करने, जवाब दाखिल करने के लिए समय देने, उस पर विचार करने और शायद सबूत का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करने और उसके बाद निर्णय लेने के लिए इसे आयात किया जा सकता है।
वास्तव में इस प्रकृति के एक उभरते प्रावधान के उद्देश्य को पराजित करने का कारण बनता है। यदि ऐसा है, तो यह भी उतना ही अच्छी तरह से तय है कि एक निर्माण जो विधायिका के इरादे को आगे बढ़ाने के बजाय पराजित करेगा, अनिवार्य रूप से टाला जाना चाहिए।

(7) हरियाणा राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री ए. एस. नेहरा ने भी इस संदर्भ में सेवा मामलों की उपमा पर जोरदार तर्क दिया। यह ठीक ही कहा गया है कि सेवा कानून के सभी पहलुओं में किसी लोक सेवक का निलंबन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है जिसके लिए यह अपेक्षित हो कि निलंबन के आकस्मिक कार्य से पहले कारण बताओ नोटिस भी दिया जाए। वकील ने सही तर्क दिया कि प्रबंध समिति के सदस्य का निलंबन हालांकि समान नहीं है, लेकिन यह समान स्तर पर है। यह भी बताया गया कि विधायिका ने प्रबंध समिति के साथ-साथ एक व्यक्तिगत सदस्य के रूप में भी सुपरसेशन और निलंबन के समान प्रावधान किए हैं। इस आधार पर यह बलपूर्वक प्रस्तुत किया गया था कि नोटिस के प्रावधान और कारण बताओ नोटिस के प्रावधान विधायिका द्वारा निलंबन के चरण में परिकल्पित कार्रवाई की आकस्मिक और तत्काल प्रकृति के संदर्भ में असंगत हैं।

(8) अब दो निर्णयों पर आते हुए, जिनकी शुद्धता विचाराधीन है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये स्पष्ट रूप से पहली धारणा पर हैं, और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, केवल गति चरण में दर्ज किया गया है। इसके विश्लेषण से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह मुद्दा पीठ के समक्ष गंभीर रूप से उत्तेजित होने से बहुत दूर था। विशेष रूप से टिप्पणियों में। *शादीपुर सहकारी ऋण और सेवा समिति का मामला* (1 सुप्रा) स्पष्ट रूप से पूरी तरह से संक्षिप्त है और ऐसा प्रतीत होता है कि यहां तक कि भौतिक संशोधनों को भी उनके लॉर्डशिप के ध्यान में नहीं लाया गया था। *अंगरेज सिंह के मामले* में उसी पीठ ने केवल अपनी पहले की टिप्पणी का पालन करने का विकल्प चुना था और यहां फिर से प्रतिवादियों की ओर से मामले को इसके सभी पहलुओं में बलपूर्वक प्रस्तुत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, उप-धारा (1) में उप-धारा (1) के विपरीत-भेद में उपयोग की जाने वाली शब्दावली में महत्वपूर्ण अंतर बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। निलंबन के संबंध में प्रावधान की तात्कालिक प्रकृति और यह तथ्य कि यह प्रबंध समिति के अधिक्रमण और हटाने के व्यापक संदर्भ में एक कदम है, जिसका भी उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें अंततः पार्टियां कारण बताने की हकदार हैं। *अंग्रेज सिंह के मामले* (सुप्रा)

पर भरोसा करते हुए, *लिटिल गिब्स* को-ऑप *हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बॉम्बे और एक अन्य* बनाम *महाराष्ट्र राज्य और अन्य*[3] पारित किया गया । यह याद रखने योग्य है कि वह मामला निलंबन का नहीं बल्कि सुपरसेशन का था और संबंधित क़ानून की धारा 78 में कारण बताने का अवसर प्रदान किया गया था। इसलिए, उक्त निर्णय की टिप्पणियों से दोनों मामलों में निलंबन के संबंध में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण में कोई मदद नहीं मिलती है।

(9) डिवीजन बेंच ने तब ग्राना पंचायत अधिनियम की धारा 102 के तहत इस न्यायालय में स्थापित कानून को इस आधार पर अलग करने का प्रयास किया था कि एक सरपंच के पास मौद्रिक हिस्सेदारी थी, जबकि सहकारी समिति के सदस्य या उसके प्रबंध समिति के पास सोसाइटी के व्यवसाय के प्रबंधन में वित्तीय हित थे। इस संबंध में, मेरा विचार है कि यह विचार एक ऐसे क़ानून के निर्माण के मामले में पूर्व-विशिष्ट रूप से प्रासंगिक नहीं होगा, जिसमें भाषा, यदि *परिमटेरिया* में नहीं है, तो कम से कम अनुरूप है।

(10) सिद्धांत और औचित्य के अलावा, इस न्यायालय के भीतर अनुरूप प्रावधान पर अधिकार की अधिकता भी प्रतीत होती है। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 102 (1) इसी तरह एक पंच को हटाने के लिए उसके खिलाफ शुरू की गई जांच के दौरान उपायुक्त को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रावधान एक समान प्रकृति के हैं, यह प्रकट प्रतीत होता है। उक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने ***राजिंदर सिंह* बनाम *पंचायत पंजाब के निदेशक,***[4] *मामले में यह निर्णय लिया।* को यह देखने का अवसर मिला कि उक्त धारा ने निलंबन का आदेश पारित करने से पहले कोई नोटिस देने की बात नहीं की थी और उसमें प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत को पढ़ने का विकल्प नहीं चुना था। इसी तरह के अवलोकन शमशेर बहादुर, जे. ने ***रत्ती राम* बनाम *उपायुक्त, पटियाला***[5] *में किए,* कोशल, जे. (जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) *ने* ***गुरदयाल सिंह* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य***[6] के मामले में को इसी तरह ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 102 (1) का अर्थ लगाने का अवसर दिया था और कहा था कि किसी पंच के खिलाफ निलंबन का आदेश पारित करने से पहले अवसर की कोई सूचना कानून द्वारा आवश्यक नहीं थी। अंत में इस संदर्भ में डिवीजन बेंच का निर्णय है

[3] ए.आई.आर. 1972 बोम., 108.
[4] 1963 पी.एल.आर. 1085.
[5] 1965 पी.एल.आर.
[6] 1971 पी.एल.जे. 417

*हरि सिंह* बनाम *पंचायत निदेशक, पंजाब,* (7) जिसमें यह देखा गया था: –

> * याचिकाकर्ता के निलंबन का आदेश जांच के लंबित रहने के दौरान पारित किया गया था, जिसे पंचायत निदेशक ने 30 नवंबर, 1971 के अपने पत्र के माध्यम से अधिनियम की धारा 102 (2) के तहत आदेश दिया था। प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए उपायुक्त के लिए निलंबन का आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था।

(11) इसलिए, यह स्पष्ट है कि *शादीपुर सहकारी ऋण समिति और अंगरेज सिंह के मामलों* (सुप्रा) दोनों में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण प्रासंगिक प्रावधानों के सीएफलॉस विश्लेषक, सिद्धांत रूप में जांच और इस न्यायालय के भीतर अधिकार के भार पर टिकाऊ नहीं है। इसलिए, हम दोनों निर्णयों को कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करने के रूप में खारिज करने के लिए मजबूर हैं।

(12) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए एकमात्र तर्क को नकारात्मक कर दिया गया है, इस रिट याचिका में कोई दम नहीं है जिसे परिणामस्वरूप खारिज कर दिया गया है। हालांकि, हम पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देंगे।

---

**अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।**

**रजत अरोड़ा**
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**
**चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी**